

NCST का 22वाँ स्थापना दविस

प्रलिमिंस के लयि:

[राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग](#), [अनुसूचति जनजात](#), [अनुसूचति जात](#), [ST से संबंघति प्रावधान](#)

मेन्स के लयि:

जनजातीय कल्याण में NCST का महत्त्व, अनुसूचति जनजातियों के अधिकारों की रक्षा

[स्रोत: पी.आई.बी](#)

चर्चा में क्यों?

[राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग \(NCST\)](#) ने अपना 22वाँ स्थापना दविस (19 फरवरी) मनाया, जसिमें [अनुसूचति जनजातियों \(ST\)](#) के अधिकारों की रक्षा में आयोग की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग के बारे में मुख्य बदि क्या हैं?

- **उत्पत्त और वकिस:** वर्ष 1992 में अनुसूचति जातियों (SC) और ST के लयि एक वैधानकि राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। बाद में, ST की वशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधति करने के लयि, 19 फरवरी, 2004 को 89वें संवधान संशोधन अधनियिम के माध्यम से अनुच्छेद 338 में संशोधन करके तथा संवधान में अनुच्छेद 338A जोड़कर NCST की स्थापना की गई।
- **संरचना और कार्यकाल:**
 - संरचना: NCST में एक अध्यक्ष (कैबनेट मंत्री स्तर), एक उपाध्यक्ष (राज्य मंत्री स्तर) और तीन सदस्य (सचवि स्तर) होते हैं, जनिहें राष्ट्रपतिद्वारा नयुक्ति कयिा जाता है।
 - कम-से-कम एक अन्य सदस्य महिला होनी चाहयि।
 - कार्यकाल और पुनरनयुक्ति: सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। कसिी सदस्य को अधिकतम दो कार्यकाल के लयि पुनरनयुक्ति कयिा जा सकता है।
 - प्रमुख कार्य: अनुच्छेद 338A(5) के तहत, NCST ST के लयि संवधानकि सुरक्षा उपायों की नगिरानी, जनजातीय अधिकारों के मुद्दों को संबोधति तथा सामाजकि-आर्थकि वकिस पर सलाह प्रदान करता है।
 - जनजातीय कल्याण पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है, नीतगित उपाय सुझाता है, तथा अनुसूचति जनजात कल्याण कार्यक्रमों की देखरेख करता है।
 - इसके अतरिकित, NCST (अन्य कार्यों का वनरिदेश) नयिम, 2005 के अंतर्गत, आयोग आदविसयिों के लयि भूमि स्वामतित्व अधिकारों (वन अधिकार अधनियिम, 2006) की सफिरशि करता है, तथा वैकल्पकि आजीवकि रणनीतयिों का सुझाव प्रदान करता है।
 - पंचायत (अनुसूचति कषेत्रों तक वसितार) अधनियिम, 1996 (पेसा) के पूरण कार्यान्वयन का समर्थन, तथा स्थानांतरति खेती को कम करने तथा समाप्त करने के समाधान की मांग की।

भारत में अनुसूचति जनजातयिों से संबंघति प्रावधान कौन-से हैं?

और पढ़ें.. [भारत में अनुसूचति जनजातयिों से संबंघति प्रावधान](#)

NCST से संबंघति चुनौतयिाँ क्या हैं?

- **प्रशासनकि और वतितीय बाधाएँ:** NCST जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जसिमें वतितीय और परिचालन स्वायत्तता का अभाव है, जसिसे बजट तथा संचालन में इसकी स्वतंत्रता प्रभावति होती है।
 - संवधान के अनुच्छेद 338A(9) में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य सरकारें अनुसूचति जनजातयिों को प्रभावति करने

वाले सभी प्रमुख नीतितगत मामलों पर NCST से परामर्श करेंगी।

- हालाँकि, अनेक राज्य और वभाग यह परामर्श करने में वफिल रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी जनजातीय कल्याण नीतियों का निर्माण होता है जिनमें आयोग की भूमिका नहीं होती है।

■ **जनशक्तिका अभाव:** NCST जनजातीय कल्याण योजनाओं की समीक्षा करता है, लेकिन सीमति कर्मचारियों और खराब समन्वय के कारण इसकी प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न होता है।

- ऐतिहासिक दृष्टिसे, NCST में प्रमुख पदों जैसे- अध्यक्ष और सदस्यों की लंबे समय से रिक्तियाँ बनी हुई हैं।

- जनशक्तिके अभाव और नौकरशाही देरी के कारण समाधान में लंबा समय लग जाता है, जिससे कई मामले वर्षों तक लंबित रह जाते हैं और जनता का विश्वास प्रभावित होता है।

■ **कमज़ोर प्रवर्तन शक्तियाँ:** NCST की सफारिशें आबद्धकर नहीं हैं, जिससे अनुसूचित जनजातियों के लिये सुरक्षात्मक उपायों का क्रियान्वन करने की इसकी क्षमता सीमति हो जाती है।

- जनजातियों के वरिद्ध अत्याचार, भूमि के अन्यासंक्रामण (Alienation) और आरक्षण लाभ से वंचित करने के संबंध में अनेक याचिकाएँ प्राप्त होने के बावजूद NCST के पास स्वयं के निर्देशों का क्रियान्वन करने की शक्तिका अभाव है।

- इससे इसका (आयोग) का प्राधिकार प्रभावित होता है और सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही कम होती है।

■ **जागरूकता और जनसंपर्क का अभाव:** अनेक जनजातीय समूह अपने अधिकारों और NCST के अस्तित्व से अनभिज्ञ हैं जो दर्शाता है कि आयोग की मूल स्तर पर मज़बूत उपस्थितिका अभाव है।

आगे की राह

- **वधिक अधिदेश का सुदृढीकरण:** NCST को [सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005](#) के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वन के संदर्भ में [केंद्रीय सूचना आयोग](#) को दी गई शक्तियों की तर्ज पर दंड अधिपति किये जाने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिये।
- **क्षमता निर्माण:** NCST में स्टाफ की कमी से इसके संचालन को अप्रभावित रखने हेतु इसके **कर्मियों** के लिये एक अलग कैडर बनाया जाना चाहिये।
- **नीतियों पर अनविर्य परामर्श:** सरकार को अनुच्छेद 338A(9) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये, जिससे मंत्रालयों और राज्यों के लिये सभी जनजातीय कल्याण नीतियों पर NCST से परामर्श करना अनविर्य हो जाए।
- **शकियतें:** NCST के पास हिसा, वसिस्थापन और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर कार्रवाई के लिये एक **समर्पति शकियत नविवरण प्रकोष्ठ** होना चाहिये।

???????? ???? ???? ????:

प्रश्न. राष्ट्रिय अनुसूचित जनजात आयोग का अधिदेश क्या है? जनजातीय अधिकारों की रक्षा में इसकी प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????????:

प्रश्न. यद किस्सी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संवधान की पाँचवी अनुसूची के अधीन लाया जाए, तो नमिनलिखित कथनों में कौन-सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? (2022)

- (a) इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर-जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी।
- (b) इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा।
- (c) इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा।
- (d) ऐसे क्षेत्रों वाले राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किया जाएगा।

उत्तर: (a)

????????:

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये राज्य द्वारा की गई दो प्रमुख वधिक पहलें क्या हैं? (2017)

